गतिविधि बुलेटिन

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनावों में दिशा छात्र संगठन का दूसरा सफल हस्तक्षेप

3 सितम्बर को दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव सम्पन्न हुए। इस बार भी दिशा छात्र संगठन ने इन चुनावों में हस्तक्षेप कर अपनी उपस्थिति दर्ज करायी। ज्ञात हो कि पिछली बार दिशा छात्र संगठन ने पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनावों में हस्तक्षेप किया था और पहले हस्तक्षेप में ही बड़े पैमाने पर छात्रों का समर्थन प्राप्त किया था। इस बार दिशा छात्र संगठन को चुनावों से पहले ही प्रशासनिक तानाशाही का शिकार होना पड़ा और उसके दो नामांकन (अध्यक्ष के लिए कुणाल जैन और सहसचिव के लिए खुशमिता कौशिक) दिखावटी आधारों पर रद्द कर दिये गये। फिर भी दिशा छात्र संगठन ने सिर्फ़ दो उम्मीदवारों के साथ चुनावों में हस्तक्षेप किया और पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करते हुए उपाध्यक्ष पद के लिए 1000 और सचिव पद के लिए 1300 वोट प्राप्त किये। उपाध्यक्ष पद के लिए दिशा छात्र संगठन की तरफ़ से नवनीत प्रभाकर और सचिव पद के लिए शमीम खड़े हुए।

दिशा छात्र संगठन ने इस बार भी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से एजेण्डा-आधारित चुनाव भागीदारी करने की अपील की और आह्वान किया कि छात्रसंघ को क्रान्तिकारी राजनीति का केन्द्र बनायें, न कि सांसद-विधायक बनने का प्रशिक्षण केन्द्र। दिशा ने एक 10-सूत्रीय माँगपत्रक पेश किया। इसमें पिछले वर्ष की ही तरह वित्तीय पारदर्शिता, हॉस्टल बनवाने, यू-स्पेशल बसें चलवाने, मेट्रो में छात्र पास की व्यवस्था लागू करने के साथ ही सेमेस्टर प्रणाली लागू करने का विरोध किया और साथ ही कॉमनवेल्थ खेलों के नाम पर छात्रों को छात्रावासों से बेदख़ल किये जाने का विरोध किया और निकाले गये छात्रों को मुआवज़ा देने की माँग की। मतदान से दो दिन पहले दिशा छात्र संगठन ने नॉर्थ कैम्पस में एक रैली का आयोजन किया और इसके ज़रिये अपने माँगपत्रक को आम छात्रों तक पहुँचाया। चुनावों के नतीजे 5 तारीख़ को घोषित हुए। दिशा छात्र संगठन ने अपने स्थान में पिछली बार के मुक़ाबले सुधार किया है। पिछले वर्ष उसके तीन उम्मीदवार 7वें, 7वें और 8वें स्थान पर थे, जबकि इस बार उसके दो उम्मीदवार 6वें और 7वें स्थान पर रहे। दिशा के दिल्ली इकाई के समन्वयक कुणाल ने उम्मीद जतायी कि आने वाले समय में दिशा छात्र संगठन छात्र राजनीति में एक क्रान्तिकारी विकल्प बनकर उभरेगा।

'आज़ादी के 63 साल और हम' पर गोष्ठी का आयोजन

15 अगस्त, 2010 को शहीद भगतसिंह पुस्तकालय, करावल नगर में आज़ादी के 63 बरस पूरे होने के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का विषय था – 'आज़ादी के 63 साल और हम'। कार्यक्रम की शुरुआत 'तोड़ो बन्धन-तोड़ो' नामक क्रान्तिकारी गीत से की गयी। तदुपरान्त दिशा छात्र संगठन के साथी प्रशान्त ने अपना सारगर्भित वक्तव्य प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त, 1947 को हिन्दुस्तान औपनिवेशिक शिकंजे से तो मुक्त हुआ लेकिन यह आज़ादी हमें कुछेक महान नेताओं या धनिकों की समझौतापरस्ती भरी कारगुजारियों के चलते नहीं बल्कि देश के मेहनतकश अवाम की अकूत कुर्बानियों के बूते मिली। तमाम नौजवानों, मज़दूरों और किसानों के सतत् संघर्ष और व्यापक दबाव के चलते ही ब्रितानी हुकूमत को अपना बोरिया-बिस्तर बाँधकर यहाँ से रुख़सत होना पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य से मज़दूरों, किसानों की नेतृत्वकारी ताक़तों की कमज़ोरी के चलते आन्दोलन की बागडोर पूँजीपति वर्ग की नुमाइन्दगी करने वाली पार्टी कांग्रेस के हाथों में ही रही। अन्ततः सत्ता की बागडोर गोरे शासकों की जगह देश के भूरे शासकों के हाथों में आ गयी। यही वर्ग आज जश्न में डूबा आज़ादी का ढोल बजा रहा है, देश के विकास का आँकड़ा परोस रहा है। आज़ादी के नाम पर इस देश के ग़रीबों को महज़ जूठन नसीब हुई है। इस देश की हुकूमत ने सत्ता व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखते हुए उन्हीं नियम-कायदों को बरकरार रखा है जिन नियम-कायदों के बूते अंग्रेज़ इस देश को 250 साल तक गुलाम बनाये रखे। वही सीआरपीसी, आईपीसी, नौकरशाही और साथ में वही दमनतन्त्र। आये दिन 'आज़ादी' का असली रंग दिखायी पड़ जाता है। वह चाहे मज़दूरों के अपने हक़ की माँगें हो या आम ग़रीब किसानों का जायज़ लड़ाई, यह शासन तन्त्र अपने फ़ौज-फाटे का इस्तेमाल बेरहमी से करने में क़तई नहीं चूकता है। ऐसे में हम यही कह सकते हैं कि अभी यह आज़ादी अधूरी है। मुकम्मल आज़ादी के लिए हमें एक बार फिर लामबन्द होना होगा।

दिशा छात्र संगठन के साथी शमीम ने कहा कि आज पूरे देश के कोने-कोने में मुट्ठी भर देशी-विदेशी धनपशुओं के हित के लिए ग़रीबों, किसानों और आदिवासियों को उनकी जगह-ज़मीन से उजाड़ा जा रहा है। प्रतिरोध करने वाली ताक़तों को सरकार और सरकारी भोंपू देशद्रोही और आतंकवादी आदि घोषित कर रहे हैं। यह सच है कि आज के नक्सलवाद के पास न सही विश्लेषण है और न सही विकल्प। लेकिन आज अगर उनके पीछे आदिवासियों का एक हिस्सा खड़ा है तो इसका कारण उस क्षेत्र में मुनाफ़े की ख़ातिर राज्य द्वारा फैलाया गया आतंक है। साथी नवीन ने अली सरदार जाफ़री की मशहूर नज़्म 'कौन आज़ाद हुआ' का पाठ किया। दिशा के साथी नवनीत ने बाबा नागार्जुन की कविता 'किसकी है जनवरी किसका अगस्त है' को पढ़ा। कविता-पाठ को श्रोताओं ने काफ़ी पसन्द किया। विचार गोष्ठी का संचालन नौजवान भारत सभा के योगेश ने किया। कार्यक्रम की समाप्ति 'तस्वीर बदल दो दुनिया की' गीत गाकर किया गया। देर शाम को रूसी मज़दूर क्रान्ति पर आधारित फिल्म 'दस दिन जब दुनिया हिल उठी' का प्रदर्शन किया गया।

बीएचयू प्रशासन का 'दख़ल' पर हमला....

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) देश का ऐसा सुप्रसिद्ध अकादमिक प्रतिष्ठान है, जो नयी-नयी उपलब्धियाँ हासिल करने के कारण लगातार सुर्ख़ियों में बना रहा है, वहीं पिछले दिनों एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने प्रतिष्ठान के तानाशाही चरित्र को दिन के उजाले की तरह साफ़ कर दिया। गत जुलाई माह में बीएचयू के कुछ छात्रों द्वारा 'दख़ल' नाम की दीवार पत्रिका की शुरुआत की गयी। इसका उद्देश्य था देश-दुनिया के प्रगतिशील रचनाकारों के विचारों को आम छात्र-छात्राओं तक पहुँचाना। समाज के ज्वलन्त मुद्दों पर छात्रों-नौजवानों के सामने एक सवाल खड़ा करना। आज के हालात एवं उनके कारणों की पड़ताल करने की दृष्टि से 'दख़ल' को छात्रों के बीच लाया गया था। दीवार पत्रिका के लग जाने के कुछ ही घण्टों बाद उसे लगाने वाले छात्रों के पास प्रॉक्टर ऑफ़िस की ओर से धमकी भरा फ़ोन आया। उनसे कहा गया कि विश्वविद्यालय परिसर में विचारधारात्मक

प्रचार नहीं किया जा सकता और चेताया गया कि दीवार पत्रिका के माध्यम से हम यह कार्यवाही आगे से न करें। प्रशासन के इस क़दम ने उसे कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल यह उठता है कि एक दीवार पत्रिका से प्रशासन को क्या आपत्ति है और प्रशासन किस तरह के विचारधारात्मक प्रचार का विरोध कर रहा है?

प्रशासन द्वारा उठाया गया यह क़दम उसके तानाशाहीपूर्ण रवैये की ही अभिव्यक्ति है। प्रशासन छात्रों की अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन करने में ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करता है। बीएचयू परिसर में पिछले कई वर्षों से यह माहौल व्याप्त है। छात्रों के अधिकारों को तरह-तरह से कुचलने की कोशिश की जाती रही है। इसका एक उदाहरण तो यह है कि विश्वविद्यालय में छात्रों के पास ऐसा कोई मंच मौजूद नहीं है जिसके ज़रिये वे अपने मुद्दों को उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की औपचारिकता को पूरा करने के लिए "छात्र परिषद" जैसे एक मंच का गठन किया गया है जिस पर तमाम अध्यापकों का वर्चस्व क़ायम है। ऐसे में स्पष्ट है कि छात्रों के पास अपना ऐसा कोई मंच मौजूद नहीं है, जहाँ से वे अपने प्रतिरोध एवं मुद्दों को उठा सकें। प्रशासन द्वारा उठाया गया यह क़दम छात्रों को छात्रसंघ के उस अधिकार से वंचित करता है जो उन्होंने एक समय में अकूत कुर्बानियाँ देकर हासिल किया था।

बीएचयू प्रशासन ने किसी ख़ास विचारधारा पर आपत्ति जतायी है। प्रश्न यह है कि आख़िर प्रेमचन्द, ब्रेख़्त, मुक्तिबोध जैसे रचनाकारों के विचारों से प्रशासन को भला क्या परेशानी है? कारण यह है कि ये तमाम साहित्यकार यथास्थिति के विरुद्ध बात करते हैं, शोषण पर क़ायम सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था की मुखर आलोचना करते हैं, एक बेहतर समाज की कल्पना करते हैं। सम्भव है कि ये उम्मीद भरे विचार छात्रों-छात्राओं की आबादी को प्रभावित करें, उन्हें इस व्यवस्था पर सवाल उठाने को बाध्य कर दें। छात्र आबादी किसी भी प्रकार का कोई प्रतिरोध ज़ाहिर करे, यह प्रशासन नहीं चाहता। वह नहीं चाहता कि छात्र-युवाओं की आबादी किसी भी तरह के सामाजिक परिवर्तन का सपना देखे। ग़ौरतलब है कि जनवादी स्पेस को संकुचित करने की मुहिम देशभर के अधिकांश विश्वविद्यालयों में आज ज़ोर-शोर से चलायी जा रही है। छात्र-छात्राओं को संवदेनशील, इंसाफ़पसन्द, तार्किक बनाने में विश्वविद्यालयों ने एक ऐतिहासिक भूमिका निभायी है, मगर आज इस ज़िम्मेदारी को भुला दिया गया है। ऐसे समय में यह तय करने की ज़िम्मेदारी हम नौजवानों के कन्धों पर है कि ऐसे माहौल को चुपचाप बर्दाश्त करना चाहते हैं या इसे बदलने के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं!

गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन की तानाशाही के विरुद्ध दिशा का आन्दोलन

गोरखपुर विश्वविद्यालय में नये सत्र के प्रवेश प्रारम्भ होने पर दिशा छात्र संगठन द्वारा नये प्रवेशार्थियों के लिए सहायता केन्द्र लगाकर सहायता पुस्तिका का वितरण किया जा रहा था। हर बार की तरह इस बार भी गो.वि.वि. का सत्र देर से शुरू हुआ था। अभी तक स्नातक, परास्नातक के आधे परीक्षा परिणाम भी नहीं निकले हैं। स्वागत पुस्तिका में उठाये गये छात्र हितों तथा भ्रष्टाचार के मुद्दे विश्वविद्यालय को पहले ही दिन से खटकने लगे। अगले ही दिन प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्य आकर दिशा कार्यकर्ताओं को स्वागत पुस्तिका बाँटने से रोकते हुए कहने लगे कि विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार के पर्चे, आदि बाँटना, पोस्टर लगाना, सभा करना मना है। इस पर दिशा ने विरोध किया। उसके बाद मुख्य नियन्ता अपने दल-बल के साथ आये तथा पुलिसिया अन्दाज़ में गाड़ी से उतरते हुए दिशा छात्र संगठन के सदस्यों के साथ धक्का-मुक्की करते हुए जीप में जबरिया बैठाकर ले जाने लगे। प्रोक्टोरियल बोर्ड के एक सदस्य ने कहा कि ये सब नक्सली है इनको ठीक कर दिया जायेगा। जीप में ही नारेबाज़ी और विरोध करने पर मुख्य नियन्ता ने कार्यकर्ताओं को विश्वविद्यालय के मुख्यद्वार पर लाकर छोड़ दिया। मुख्यद्वार पर दिशा छात्र संगठन से सभा करनी शुरू कर दी। काफ़ी देर तक प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों के साथ नोंक-झोक होती रही। फिर प्रोक्टोरियल बोर्ड को पीछे हटना पड़ा। सभा को सम्बोधित करते हुए दिशा के संयोजक अपूर्व मालवीय ने कहा कि विश्वविद्यालय में पर्चा बाँटने से रोकना, सहायता केन्द्र लगाने से मना करना, छात्रों की आवाज़ दबाना या छात्रों के जनतान्त्रिक अधिकारों पर हमला है। विश्वविद्यालय प्रशासन आकण्ठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और वह नहीं चाहता है कि उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाये।

सभा में राजू ने बताया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन का तानाशाहीपूर्ण रवैया पिछले लम्बे समय से जारी है। विश्वविद्यालय का संवाद भवन सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र रहा है, जिसको छात्र प्रतिनिधियों को निःशुल्क तथा अन्य लोगों को न्यूनतम शुल्क पर दिया जाता था। लेकिन इस तरह की गतिविधियों के लिए उसको प्रतिबन्धित कर दिया है। अब इस विश्वविद्यालय में पर्चा बाँटना, पोस्टर लगाना भी ग़ैर-क़ानूनी हो गया है। उच्च शिक्षा के परिसरों में लगातार जनतान्त्रिक अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। कैम्पसों को पुलिस छावनी में बदला जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार के दमन-उत्पीड़न का छात्र जबाब न दे सकें। वीरेश ने कहा कि जब तक मुख्य नियन्ता को बर्ख़ास्त नहीं किया जाता, तब तक हम अपने आन्दोलन को जारी रखेंगे। अगले दिन विश्वविद्यालय के मुख्यद्वार पर दिशा ने आम छात्रों के साथ एक ज़ोरदार प्रदर्शन कर चार सूत्रीय ज्ञापन कुलपति को सौंपा। दिशा ने कैम्पस में जाकर छात्रों की सहायता की तथा उनके बीच स्वागत पुस्तिका का वितरण शुरू कर दिया। फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग आकर आम छात्रों, उनके अभिभावकों के साथ-साथ दिशा कार्यकर्ताओं को भगाने लगे जिस पर आम छात्रों तथा दिशा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। विश्वविद्यालय प्रशासन से यह नोंक-झोक दिन भर चलती रही और कैम्पस के अन्दर पुस्तिका का वितरण होता रहा। विश्वविद्यालय के इस गैर-जनतान्त्रिक रवैये की शहर के नागरिकों तथा बुद्धिजीवियों ने आलोचना करते हुए एक निन्दा प्रस्ताव पारित किया जिसमें साहित्यकार परमानन्द श्रीवास्तव, गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफ़ेसर रामकृष्ण मणि त्रिपाठी, पत्रकार एवं गोरखपुर फ़िल्म सोसाइटी के संयोजक मनोज कुमार सिंह, कथाकार मदन मोहन, कवि देवेन्द्र आर्य, कार्टूनिस्ट एवं फ़िल्मकार प्रदीप सुविज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार गिरिजेश राय, ट्रेड यूनियन कर्मी शिव नन्दन सहाय, संस्कृतिकर्मी डॉ. मुमताज ख़ान, पंत्रकार स्वदेश कुमार, साहित्यकार जगदीश नारायण श्रीवास्तव, प्रवक्ता डॉ. अंगद कुमार सिंह आदि लोग शामिल थे।